लाल शाह बाबा दरगाह ट्रस्ट

बनाम

मैगनम डेवलपर्स और अन्य

(सिविल अपील संख्या 14565/ 2015)

15 दिसंबर, 2015

[एम. वाई. इक्बाल और सी. नागप्पन, जे. जे.]

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (2013 अधिनियम द्वारा संशोधित) - न्यायाधिकरण का गठन-धारा 83 (4) में संशोधन जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा-क्या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन होने तक 1995 के अधिनियम के तहत गठित एक सदस्य न्यायाधिकरण काम करता रहेगा या इसका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा-यह आम बात है कि राज्य ने धारा 83 के तहत प्रदान की गई तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने वाली नई अधिसूचना जारी करने का अपना अनिवार्य कर्तव्य नहीं निभाया है-यह आम बात है कि पुरानी संस्था/सदस्य तब तक कर्तव्य का पालन करते रहते हैं जब तक कि कोई नई संस्था/सदस्य उस कर्तव्य का कार्यभार संभालता है-एक सदस्य न्यायाधिकरण उस समय तक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता रहेगा जब तक कि राज्य अधिसूचना द्वारा

तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं करता है। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (2013 अधिनियम द्वारा संशोधित) - न्यायाधिकरण का गठन-धारा 83(4) में संशोधन जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा-क्या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन होने तक 1995 के अधिनियम के तहत गठित एक सदस्य न्यायाधिकरण काम करता रहेगा या इसका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा-यह आम बात है कि राज्य ने धारा 83 के तहत प्रदान की गई तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने वाली नई अधिसूचना जारी करने का अपना अनिवार्य कर्तव्य नहीं निभाया है-यह आम बात है कि पुरानी संस्था/सदस्य तब तक कर्तव्य का पालन करते रहते हैं जब तक कि कोई नई संस्था/सदस्य उस कर्तव्य का कार्यभार संभालता है-एक सदस्य न्यायाधिकरण उस समय तक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता रहेगा जब तक कि राज्य अधिसूचना द्वारा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं करता है।

सिद्धांत/सिद्धांत-निहित निरसन का सिद्धांत-आवेदन-आंशिक रूप से अपीलों की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों और कारणों के बयान के अवलोकन से, यह पता चलता है कि न्यायाधिकरण का एकल सदस्य वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 संशोधन से पहले) के तहत ठीक

काम कर रहा था। 2013 के संशोधन द्वारा संरचना का विस्तार करने के विचार से न्यायाधिकरण में दो और सदस्यों की मदद से न्यायाधिकरण के कामकाज में सुधार होता प्रतीत होता है। यहां तक कि अधिनियम की धारा 85 में 2013 के संशोधन द्वारा, उन्होंने दीवानी अदालत के साथ-साथ राजस्व अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण के सी अधिकार क्षेत्र को भी हटा दिया है। अर्थात् विधायिका यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अधिनियम की धारा 83 के तहत गठित न्यायाधिकरण के अलावा कोई भी प्राधिकरण वक्फ संपत्ति, किरायेदार की बेदखली या इस अधिनियम के तहत ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का निर्धारण नहीं करेगा। [अनुच्छेद 25 और 26)[985-एफ-एच;986-ए]

1.2 संशोधन के अनुसार, तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाना है। हालाँकि, राज्य ने अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रदान किए गए अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन नहीं किया है (जैसा कि धारा 83 में "होगा" शब्द का उपयोग किया गया है)। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह आम बात है कि पुराना संस्थान/सदस्य तब तक कर्तव्य का पालन करता रहता है जब तक कि कोई नया संस्थान/सदस्य उस कर्तव्य का कार्यभार नहीं संभाल लेता। एक सदस्यीय न्यायाधिकरण अधिकारिता का प्रयोग तब तक जारी रखेगा जब तक कि राज्य आधिकारिक राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा तीन जी सदस्य न्यायाधिकरण का गठन नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि दीवानी न्यायालय ऐसी स्थिति में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा क्योंकि यह विधायिका के इरादे से स्पष्ट है कि वे नहीं चाहते कि कोई अन्य प्राधिकरण अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के मामले पर प्रयोग करे। [पैरा27][986-8 बी.डी.]

1.3 यह प्रस्तुत किया गया था कि 2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा, उप-धारा 83 (4) को पूर्व की उप-धारा 83 (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि विधानमंडल का इरादा है कि एक सदस्य न्यायाधिकरण पर्याप्त नहीं है और इसके स्थान पर तीन सदस्य न्यायाधिकरण कार्य करे; कि पुरानी धारा 83 (4) और संशोधित धारा 83 (4) एक दूसरे के साथ असंगत है और इसलिए, निहित निरसन का सिद्धांत लागू होगा। यह निवेदन कि 1995 की धारा 83 (4) को निरस्त किया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 28] [986-ई-जी]

1.4 यह प्रस्तुत किया गया था कि 2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा, उप-धारा 83 (4) को पूर्व की उप-धारा 83 (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि विधानमंडल का इरादा है कि एक सदस्य न्यायाधिकरण पर्याप्त नहीं है और इसके स्थान पर तीन सदस्य न्यायाधिकरण कार्य करे; कि पुरानी धारा 83 (4) और संशोधित धारा 83 (4) एक दूसरे के साथ असंगत है और इसलिए, निहित निरसन का

सिद्धांत लागू होगा। यह निवेदन कि 1995 की धारा 83 (4) को निरस्त किया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 28] [986-ई-जी]

1.5 यदि किसी विशेष अधिनियम में निरसन खंड है, तो यह स्पष्ट निरसन का मामला है, लेकिन ऐसे मामले में जहां निहित निरसन का सिद्धांत लागू किया जाना है, मामले को निरसन खंड में उपयोग किए गए शब्दों के सटीक अर्थ और दायरे को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा। निहित निरसन का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाता है और एक नए अधिनियम द्वारा एक अतिरिक्त उपचार का केवल प्रावधान एक मौजूदा उपाय को दूर नहीं करता है। निहित निरसन के सिद्धांत को लागू करते समय, यह देखना होगा कि क्या स्पष्ट रूप से असंगत प्रावधानों को निरस्त और फिर से लागू किया गया है। पूर्ववर्ती विधि के निहित निरसन का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब बाद में ऐसी विधि का अधिनियमन हो जिसमें पूर्ववर्ती विधि को ओवरराइड करने की शक्ति हो और जो पूर्ववर्ती विधि के साथ पूरी तरह से असंगत हो और दोनों विधियां एक साथ नहीं खड़ी हो सकती हैं। यदि बाद का कानून पहले के कानून का स्थान लेने में सक्षम नहीं है, और जी के लिए किसी कारण से लागू नहीं किया जा सकता है, तो पहले का कानून काम करता रहेगा। ऐसे मामले में, निहित निरसन के नियम के परिणामस्वरूप एक शून्य हो सकता है जिसका कानून बनाने वाले प्राधिकारी ने इरादा नहीं किया होगा। [पैरा 30-31] एच [987-8-एफ]

1.5 निहितार्थ द्वारा निरसन के विरुद्ध एक धारणा है। अनुमान का कारण यह है कि किसी कानून को लागू करते समय विधायिका को इस विषय पर मौजूदा कानूनों की पूरी जानकारी होती है और इसलिए, जब वह निरसन प्रावधान प्रदान नहीं कर रही होती है, तो वह मौजूदा कानून को निरस्त नहीं करने का इरादा बताती है। यदि किसी भी निष्पक्ष व्याख्या से, दोनों कानून एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो कोई निहित निरसन नहीं होगा और अदालत को निहित निरसन के खिलाफ झुकना चाहिए। इसलिए, यदि दोनों क़ानून किसी भी उचित कारण से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है और दोनों क़ानूनों को कायम रहने दिया जा सकता है। [पैरा 33] [988-जी-जी. एच.; 989-ए]

1.6 संसद का इरादा धारा 83 (4) को प्रतिस्थापित करते समय यह नहीं है कि एक सदस्य न्यायाधिकरण तब तक गायब हो जाता है या समाप्त हो जाता है जब तक कि तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो जाता। धारा 83 में नई उप-धारा (4) लाने का इरादा और कुछ नहीं बल्कि न्यायाधिकरण के गठन में सुधार है और पूर्व और प्रतिस्थापित दोनों उप-धाराएं एक दूसरे के साथ असंगत नहीं हैं। [पैरा 39] 992-सी. डी.]

1.7 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि संशोधन अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले एक सदस्यीय न्यायाधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो गया, भले ही तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने वाली एक नई अधिसूचना

को अधिसूचित नहीं किया गया हो। राज्यों ने आज तक अधिनियम की धारा 83 (4) द्वारा अनिवार्य तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए नई अधिसूचना जारी नहीं की है। राज्यों को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है और इस आशय की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। [पैरा 40,42] [992-ई, एफ, एच; 993-ए]

1.8 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम बाल मुकुंद बैरवा (2) (2009) 4 एस. सी. सी. 299:2009 (2) एस. सी. आर. 161; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2010) 8 एस. ई. सी. 24ः10 (8) एस. सी. आर. 1053; एम. पी. वक्फ बोर्ड बनाम सुभान शाह (2006) 10 एससीसी 696:2006 बी (8) पूरक एससीआर 85; नगर परिषद, पलाई बनाम टीजे जोसेफ एआईआर 1963 एससी 1561:1964 एससीआर 87; भगत राम शर्मा बनाम भारत संघ एआईआर (1988) एससी 740:88 एससीआर 1034; ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला एआईआर 1986 एससीसी 1043:1986 एससीआर 855; नगर परिषद, पलाई बनाम टीजे जोसेफ एआईआर 1963 एससी 1561:1964 एससीआर 87; हर्षद एस मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 8 एसएसईसी 257:2001 (2) पूरक एससीआर 577-डी संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2009 (2) एस. सी. आर. 161 का उल्लेख किया गया, पैरा 13

2010 (8) एस. सी. आर. 105 संदर्भित, पैरा 13

2006 (8) पूरक एस. सी. आर. 85 का उल्लेख किया गया है पैरा 14

ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1561 को संदर्भित किया गया पैरा 28

1988 एस. सी. आर. 1034 को संदर्भित किया गया, पैरा 28

1986 एस. सी. आर. 855 को संदर्भित किया गया, पैरा 32

1964 एससीआर 87 का उल्लेख किया गया है, पैरा 34

2001 (2) पूरक एस. सी. आर. 577, पैरा 36

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2015 की सिविल अपील संख्या 14565

बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2015 की सिविल संशोधन आवेदन संख्या 395 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 11-09-2015 से।

के साथ

2015 की सिविल अपील संख्या 14566, 14567, 14569, 14570 और 14571

पी. बी. गायकवाड़, वाई. एच. मुचाला, सागर ए. खान, एजाज मकबूल, सी. जॉर्ज थॉमस, आकृति चौबे, जी. डी. शेख, फराज मकबूल, सुधांशु एस. चौधरी, समीर पटेल, वात्सल्य विज्ञान, रजत कपूर, शकील अहमद सैयद, मोहम्मद परवेज डबास, उज़नी जमील हुस्सानी, शिरीष के.

देशपांडे; उपस्थित दलों के लिए अजय के. डी. जे. पनिकर, श्याम मूरजानी, सुरेशन पी., वैभव एस. नागवेकर, रवींद्र केशवराव अदसुरे, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर।

न्यायालय का निर्णय एम. वाई. इक्बाल, जे. द्वारा दिया गया था।

1. 2015 की एस. एल. पी. (सी) No.29234 विशेष अनुमति याचिका में, याचिकाकर्ता (वादी) बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2015 के सिविल संशोधन No.395 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश को चुनौती देना चाहता है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा एक सदस्य वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर वक्फ मुकदमे को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया है और शिकायत को वापस करने और विवादों के निर्णय के लिए उपयुक्त सिविल अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उक्त आदेश द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2. वादी, जिसे लाल शाह बाबा दरगाह ट्रस्ट कहा जाता है, ने एक सदस्य महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल, औरंगाबाद (संक्षेप में, "ट्रिब्यूनल") के समक्ष मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मुकदमे की संपत्ति ट्रस्ट द्वारा आयोजित वक्फ संपत्ति के रूप में है, ताकि प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रतिबंधित किया जा सके। 1 से 7 तक शहर सर्वेक्षण संख्या 1/50 से 11/50 में वादी भूखंड के अवैध रूप से विकसित हिस्से और तावरीपाड़ा, लालबाग, मुंबई में स्थित शहर सर्वेक्षण संख्या 50 के हिस्से से तीसरे पक्ष के हित पैदा करने वाले आगे के निर्माण को बढ़ाने

से; सूट संपत्तियों की प्रकृति को बदलने और उसमें निर्मित फ्लैटों का कब्जा सौंपने से भी। न्यायाधिकरण के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक अलग आवेदन भी दायर किया गया था, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और उन शर्तों में एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है।

3. न्यायाधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले आदेश से व्यथित, प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (9) के तहत सिविल संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे 2015 के सी. आर. No.395 के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों ने, अन्य बचाव पक्ष के अलावा, एक व्यक्ति न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी कि 1995 के अधिनियम की धारा 83 (4) के तहत गठित एकल सदस्य न्यायाधिकरण के कामकाज का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। 1995 के अधिनियम को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया था, जो एक व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा शुरू होने से बहुत पहले यानी 1.11.2013 से प्रभावी हुआ था।

4. उच्च न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद नागरिक पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण के आदेश को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अंततः निर्णय दियाः -

"74. अब उन मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों के भाग्य पर विचार करना भी आवश्यक है जो 1.11.2013 से प्रभावी संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित किए जाते हैं। विधायिका ने कोई अस्थायी प्रावधान नहीं किया है। विधायिका ने उन मुकदमों/कार्यवाहियों के हस्तांतरण के लिए भी प्रावधान नहीं किया है जो 1.11.2013 से पहले स्थापित किए गए हैं। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (ई) को ध्यान में रखते हुए, 1.11.2013 से पहले एकल सदस्य न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित मुकदमे/कार्यवाही को ऐसे जारी रखा जाएगा जैसे कि धारा 83 (4) में संशोधन नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वादी द्वारा एकल सदस्य न्यायाधिकरण के समक्ष 1.11.2013 के बाद दायर किया गया वक्फ मुकदमा विचारणीय नहीं है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाएं 19 और 30 प्रदर्शित आवेदनों के साथ वापस की जानी चाहिए। पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष तब उपस्थित होंगे जब न्यायाधिकरण आवेदनों के साथ याचिका को वापस करने के लिए आगे के आदेश पारित करेगा-इसमें की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 19 और 30 को प्रदर्शित करें। विवादित आदेश को रद्द करना होगा और इस आधार पर अलग करना होगा कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है और वादी द्वारा दायर आवेदन-प्रदर्शनी-19 और प्रदर्शनी-30 फाइल में बहाल किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। उक्त आवेदनों का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा आवेदनों

के प्रदर्शन 19 और 30 के साथ याचिका की वापसी के बाद, उनके अपने गुण-दोष पर और की गई टिप्पणियों से अप्रभावित कानून के अनुसार करना होगा।

75. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, सिविल संशोधन आवेदन की अनुमति निम्नानुसार दी गई हैः-

1. एकल सदस्य न्यायाधिकरण के समक्ष वादी द्वारा स्थापित वक्फ मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है और इसके परिणामस्वरूप आवेदन-प्रदर्शनी 19 और 30 के साथ शिकायत को उपयुक्त दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जा सकता है। पक्षकार 1 तारीख को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे और न्यायाधिकरण पक्षकारों के उपस्थित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

2. न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और इस आधार पर अलग कर दिया जाता है कि उक्त आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वादी द्वारा दायर आवेदन-प्रदर्शन-19 और 30 को फाइल में बहाल कर दिया जाता है। उक्त आवेदनों पर सिविल न्यायालय द्वारा अभिलेख पर सामग्री के आधार पर और इसमें की गई टिप्पणियों से अप्रभावित कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर मुकदमा वापस करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

3. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (ई) को ध्यान में रखते हुए उक्त न्यायाधिकरण द्वारा एकल सदस्य न्यायाधिकरण के समक्ष 1.11.2013 से पहले स्थापित मुकदमों या किसी अन्य कार्यवाही की सुनवाई जारी रहेगी।

4. 1.11.2013 को और उसके बाद, संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख होने के कारण, एकल सदस्य न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 83 (1) में निर्दिष्ट विवादों पर विचार करने और उन पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 1.11.2013 पर और उसके बाद शुरू किए गए मुकदमों या किसी भी कार्यवाही पर एकल सदस्य न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

5. सिविल न्यायालयों के पास धारा 85 के प्रतिबंध के बावजूद 1.11.2013 पर और उसके बाद शुरू किए गए मुकदमों या किसी अन्य कार्यवाही पर विचार करने और मुकदमा करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जब तक कि राज्य सरकार संशोधित धारा 83(4) के अनुसार तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी नहीं करती।

6. चूंकि संशोधन अधिनियम में लंबित मुकदमों के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए संशोधित धारा 83 (4) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद भी सिविल न्यायालयों द्वारा मुकदमों या किसी अन्य कार्यवाही की सुनवाई जारी रहेगी, जब तक कि केंद्र सरकार धारा 113 के

अनुसार हस्तक्षेप नहीं करती है या अधिनियम में उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाता है।

7. आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने के बावजूद, आक्षेपित आदेश के परिचालन भाग के खंड (2) और (3) आज से छह सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेंगे ताकि वादी उचित विज्ञापन अंतरिम प्राप्त कर सके, अंतरिम आदेश के सिविल से अंतरिम आदेश को किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस संबंध में सभी दलीलें स्पष्ट रूप से खुली रखी जाती हैं।

8. नियम को उपरोक्त शर्तों में पूर्ण बनाया गया है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।"

5. प्रतिवादी-प्रतिवादी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने भी विवादित आदेश से व्यथित होकर 2015 की एसएलपी (सी) संख्या 31610 के रूप में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। 2015 के एस. एल. पी. (सी) Nos.31605,31606 और 32595 में याचिकाकर्ता विवादित आदेश के उस हिस्से से व्यथित हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने वक्फ मुकदमे के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को विभाजित कर दिया और उन सभी मुकदमों पर निर्णय लेने के लिए दीवानी अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया।

6. 2015 के एस. एल. पी. (सी) No.30725 में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के उस हिस्से

पर हमला किया है जिसमें उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुकदमे की शिकायत दीवानी अदालत में प्रस्तुत नहीं की जाती।

7. चूँकि ये सभी विशेष अनुमति याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय से उत्पन्न होती हैं और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं, इसलिए इन आवेदनों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।

8. अनुमति स्वीकृत की गई।

9. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सागर ए. खान ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अवैध और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना होने के रूप में कहा क्योंकि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (9) के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया गया था। उच्च न्यायालय को मामले के गुण-दोष में प्रवेश नहीं करना चाहिए था और एकल सदस्य न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का निर्णय नहीं करना चाहिए था, जिसके समक्ष मुकदमा निर्णय के लिए लंबित था। विद्वान वकील के अनुसार, जब प्रतिवादी द्वारा महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम की धारा 9 (ए) सी. पी. सी. के तहत याचिका न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी, तो उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका में न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का फैसला नहीं करना चाहिए

था, जो प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश पर हमला करते हुए दायर की गई थी।

10. विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में जब तक राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम की संशोधित धारा 83 (4) के अनुसार एक न्यायाधिकरण का गठन नहीं करती है, तब तक एकल सदस्य न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 83 (1) के तहत उसे निर्दिष्ट मामलों का निर्धारण और निर्णय करना जारी रखेगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया गया था और इस आशय की अधिसूचना अधिनियम की धारा 83 (4) सहित वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए जारी की गई थी। उक्त संशोधन द्वारा न्यायाधिकरण जो पहले से ही मूल अधिनियम के तहत काम कर रहा था, जारी रहा क्योंकि तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने वाली कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की संशोधित धारा 83 (4) के संदर्भ में, राज्य सरकार को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने वाले आधिकारिक राजपत्र में एक नई अधिसूचना जारी करनी होगी। जब तक एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तब तक एक सदस्य न्यायाधिकरण काम करता रहेगा। इस संबंध में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने समान रूप से यह

विचार रखा है कि जब तक राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 83 (4) में संशोधन के संदर्भ में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया है, तब तक एक एकल सदस्य न्यायाधिकरण उसे भेजे गए प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

11. अंत में, श्री खान ने केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 14.05.2015 पर जारी एक अधिसूचना हमारे ध्यान में लाई, जिसके द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 सहित कई संशोधित अधिनियमों को निरस्त करने की मांग की गई, जो 01.11.2013 पर लागू हुआ। विद्वान वकील के अनुसार, विभिन्न संशोधन अधिनियमों को निरस्त करने वाली 2015 की केंद्र सरकार की उक्त अधिसूचना को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2013 के संशोधन को निरस्त करने वाले संशोधित अधिनियम, 2015 के बाद, एक सदस्य न्यायाधिकरण अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। 12. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 90 (1) और (3) के आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें प्रतिवादियों के अनुरोध को उक्त संशोधन आवेदन से प्रतिवादी संख्या 2-वक्फ बोर्ड का नाम हटाने की अनुमति दी गई है। विवादित आदेश वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था और केवल इसी आधार पर विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 6, धारा 7 और धारा 85 के प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहा, जो औकाफ और वक्फ संपत्तियों की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से हटा देता है क्योंकि इसके लिए केवल वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है।

12. इसके विपरीत, प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वाई. एच. मुच्छाला ने सबसे पहले तर्क दिया कि वादी ने 2013 में धारा 83 (4) में संशोधन लागू होने के बाद वक्फ मुकदमा दायर किया। एकल सदस्य न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट विवाद का निर्णय और निर्धारण नहीं कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार 1995 के अधिनियम में संशोधन करते समय विधानमंडल ने कोई अस्थायी प्रावधान नहीं किया है, इसलिए धारा 85 के तहत प्रतिबंध को वर्तमान मामले के तथ्यों और जी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से जब राज्य सरकार ने संशोधित धारा 83 (4) के संदर्भ में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की है। जब तक राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया जाता है, तब तक दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता है।

13. इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि वादी सिविल न्यायालय का रुख कर सकता है और उचित राहत प्राप्त

कर सकता है जब तक कि अधिनियम की धारा 83 (1) (4) के संदर्भ में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम बाल मुकुंद बैरवा (2), (2009) 4 एस. सी. सी. 299; और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 24 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

14. प्रतिवादियों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं किया है कि वाद की संपत्तियां वादी की वक्फ संपत्तियां हैं, और इसलिए, न्यायाधिकरण को अंतरिम आदेश देने में उचित ठहराया गया था। जबकि वादी की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि अधिनियम को लागू करना एक बात है और अधिनियम को लागू करना दूसरी बात है। यद्यपि प्रधान अधिनियम 1.1.1996 से प्रभावी हुआ और संशोधन अधिनियम 1.11.2013 से प्रभावी हुआ, अधिनियम की योजना स्वयं इस बात पर विचार करती है कि अधिनियम को चरण-वार लागू किया जाएगा। जब तक न्यायाधिकरण का गठन संशोधित धारा 83 (4) के संदर्भ में किया जाता है, तब तक एकल सदस्य न्यायाधिकरण संशोधित धारा 83 (1) के तहत विचार किए गए विवादों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रधान अधिनियम और संशोधन अधिनियम भी विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों पर

विचार करते हैं। ऐसे प्राधिकरणों में से प्रत्येक को क़ानून के चार कोनों के भीतर कार्यों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में, वादी ने एम. पी. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। वक्फ बोर्ड बनाम सुभान शाह, (2006) धारा 696

15. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने ऊपर उद्धृत किए गए विवादित आदेश के समापन पैरा 74 में कहा कि एक सदस्य न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा विचारणीय नहीं है और जब तक तीन सदस्य न्यायाधिकरण का गठन करने वाली राज्य सरकार द्वारा एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तब तक दीवानी न्यायालय को ऐसे मुकदमों पर विचार करने और वक्फ संपत्तियों के संबंध में विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक सदस्य न्यायाधिकरण द्वारा पारित निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 73 में कहाः -

"73. यह सवाल कि मुकदमों की संपत्तियां वक्फ संपत्तियां हैं या नहीं, कानून का शुद्ध सवाल नहीं है। यह कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल है। संबंधित मामले को साबित करने के लिए पक्षों को साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा। विवादित आदेश में पैराग्राफ 32 और 34 में दर्ज कारणों के लिए, न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश दिया है। मुझे नहीं लगता कि न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की

है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि प्रतिवादी नहीं। 1 से 7 ने अभ्यास 17 में आक्षेपित क्रम में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला बनाया है।"

16. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और 2013 में लाए गए मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम दोनों के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की है।

17. वक्फ अधिनियम, 1995 की एक सरसरी नज़र से पता चलता है कि वक्फ अधिनियम, (संक्षेप में '1995 अधिनियम') 1.1.1996 से लागू हुआ। धारा 3 (क्यू) द्वारा, न्यायाधिकरण को उस क्षेत्र के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा 1 के तहत गठित न्यायाधिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 84 न्यायाधिकरण को वक्फ संपत्ति से संबंधित विवाद, प्रश्नों या अन्य मामलों को तय करने और निर्धारित करने और कार्यवाही को यथासंभव तेजी से तय करने की शक्ति प्रदान करती है।

18. सुसंगत प्रावधान अर्थात धारा 83 राज्य सरकार को न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। मूल अधिनियम में, धारा 83 में केवल एक व्यक्ति वाले न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। धारा 83 की उप-धारा 4, जो मूल अधिनियम के तहत थी, नीचे उद्धृत की गई हैः-"(4) प्रत्येक न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति होगा, जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होगा, जो जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश, श्रेणी I से कम का पद धारण नहीं करेगा, और ऐसे प्रत्येक

व्यक्ति की नियुक्ति नाम या पदनाम से की जा सकती है। 2013 में 1995 के अधिनियम में कुछ संशोधन लाए गए हैं जिन्हें वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा धारा 83 सहित कई धाराओं में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद, धारा 83 निम्नानुसार हैः-"83 न्यायाधिकरणों आदि का गठन-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए, इस अधिनियम के तहत किसी किरायेदार को बेदखल करने या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए, जितने उचित समझे उतने न्यायाधिकरणों का गठन करेगी और ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थानीय सीमाओं और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करेगी; (2) वक्फ में रुचि रखने वाला कोई भी मुतवल्ली व्यक्ति या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बनाए गए आदेश से व्यथित कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उस समय के भीतर आवेदन कर सकता है। (3) जहां उप-धारा (1) के तहत किया गया कोई आवेदन किसी वक्फ संपत्ति से संबंधित है जो दो या अधिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आती है, वहां ऐसा आवेदन उस न्यायाधिकरण को किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मुतवल्ली या वक्फ के मुतवल्ली में से कोई एक

वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और जहां ऐसा कोई आवेदन न्यायाधिकरण को किया जाता है, तो अन्य न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण जो अधिकार क्षेत्र रखते हैं, ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगेः बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि यह राय हो कि यह वक्फ या किसी अन्य व्यक्ति के हित में समीचीन है।

(4) प्रत्येक न्यायाधिकरण में शामिल होंगे-(ए) एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होगा, जो जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश, वर्ग I से कम का पद धारण नहीं करेगा, जो अध्यक्ष होगा; (बी) एक व्यक्ति, जो राज्य सिविल सेवा से अतिरिक्त जी जिला मजिस्ट्रेट, सदस्य के समकक्ष पद का अधिकारी होगा; (सी) मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति, सदस्य; और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति या तो नाम से या पदनाम से की जाएगी। (4 क) पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के अलावा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्तों सहित नियुक्ति के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं। (5) न्यायाधिकरण को एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा और उसके पास वही शक्तियां होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत दीवानी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय या डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय प्रयोग की जा सकती हैं। (6) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908

का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए। (7) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और इसमें दीवानी अदालत द्वारा की गई डिक्री का बल होगा। (8) न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय का निष्पादन उस दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे ऐसा निर्णय दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन के लिए भेजा जाता है। (9) न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगीः बशर्ते कि कोई उच्च न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले से संबंधित रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है जो न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे निर्धारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है और ऐसे निर्धारण की पुष्टि, उलट या संशोधन कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

20. धारा 83 की संशोधित उप-धारा (4) के अवलोकन से पता चलेगा कि अब न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होंगे और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तीन सदस्यों वाले एक न्यायाधिकरण का गठन करेगी। निर्विवाद रूप से, आज तक, धारा 83 की संशोधित उप-धारा (4) के अनुसार, विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों ने अधिसूचना जारी करके तीन व्यक्तियों वाले न्यायाधिकरण का

गठन नहीं किया है।

21. इसलिए, विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन होने तक 1995 के अधिनियम के तहत गठित एक सदस्य न्यायाधिकरण काम करता रहेगा या उसके पास विवादों पर विचार करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

22. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 लाने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे उद्धृत किया गया हैः-'वक्फ अधिनियम, 1995, (जिसने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 को निरस्त और प्रतिस्थापित किया) 1 जनवरी, 1996 को लागू हुआ। अधिनियम में औकाफ़ के बेहतर प्रशासन और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों का प्रावधान है। हालाँकि, अधिनियम के काम करने के वर्षों में, एक व्यापक भावना रही है कि अधिनियम औकाफ़ के प्रशासन में सुधार करने में पर्याप्त प्रभावी साबित नहीं हुआ है। भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति (जिसे सच्चर समिति के रूप में भी जाना जाता है) ने 17 नवंबर, 2006 को प्रधानमंत्री को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त मुद्दे पर विचार किया और जी महिलाओं के प्रतिनिधित्व, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना की समीक्षा, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण का

मुकाबला करने के लिए एक कठोर और अधिक प्रभावी दृष्टिकोण और अन्य मामलों से संबंधित अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। समिति ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम और राज्य वक्फ विकास निगमों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इच्छित उद्देश्यों के लिए मूल्यवान वक्फ संपत्तियों के उचित उपयोग की सुविधा प्रदान की जा सके। समिति ने सिफारिश की कि अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि राज्य वक्फ बोर्ड प्रभावी हो सकें और वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को हटाने से ठीक से निपटने के लिए सशक्त हों। इसने अधिनियम में संशोधन करने की भी सिफारिश की ताकि वक्फ न्यायाधिकरण का संचालन विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के लिए नियुक्त एक पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाए। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति ने 4 मार्च, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपनी तीसरी रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध सर्वेक्षण, अतिक्रमण की रोकथाम और हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद को एक अधिक प्रभावी और सार्थक निकाय बनाने, वक्फ संपत्तियों के विकास के प्रावधानों आदि से संबंधित व्यापक संशोधनों की सराहना की। 23 अक्टूबर, 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत अपनी नौवीं रिपोर्ट में संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार किया। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा विचार किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी

अधिकारियों जैसे अन्य हितधारकों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों और अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर भी विचार किया गया है।

23. उपरोक्त उद्देश्य के साथ, मूल अधिनियम में आवश्यक प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है। विधेयक के खंड 40 में न्यायाधिकरण की संरचना का विस्तार करने की दृष्टि से न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 83 सी में संशोधन करने की मांग की गई है। विधेयक के खंड 41 में दीवानी अदालतों की अधिकारिता पर रोक से संबंधित अधिनियम की धारा 85 में संशोधन करने की मांग की गई है ताकि वक्फ से संबंधित विवादों, प्रश्न या अन्य मामलों के संबंध में दीवानी अदालतों के अलावा राजस्व अदालतों और किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बाधित किया जा सके। वक्फ संपत्तियों या अन्य मामलों को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

24. उपरोक्त उद्देश्यों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वक्फ अधिनियम, 1995 में एकल सदस्य न्यायाधिकरण के कामकाज के संबंध में कोई मुद्दा था, जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 27) के लागू होने से पहले काम कर रहा था। वे केवल वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक) के खंड 40 में उल्लिखित न्यायाधिकरण की संरचना का विस्तार करने के लिए तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का विचार लेकर आए हैं, जिसमें प्रावधान है कि यह न्यायाधिकरणों आदि के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 83 में

संशोधन करना चाहता है। राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष होगा जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होगा जो जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 से कम का पद नहीं रखेगा। दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक राज्य सिविल सेवा का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष पद का अधिकारी होगा और दूसरा मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा। उद्देश्यों और कारणों के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायाधिकरण का एकल सदस्य वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 के संशोधन से पहले) के तहत ठीक से काम कर रहा था। 2013 के संशोधन द्वारा संरचना का विस्तार करने के विचार से न्यायाधिकरण में दो और सदस्यों की मदद से न्यायाधिकरण के कामकाज में सुधार होता प्रतीत होता है। और इस अधिनियम के तहत ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के दायित्व।

27. संशोधन के अनुसार, तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाना है। हालाँकि, राज्य ने अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रदान किए गए अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन नहीं किया है (जैसा कि धारा 83 में "होगा" शब्द का उपयोग किया गया है)। फिर सवाल यह है कि क्या राज्य की निष्क्रियता के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान उठाना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह आम बात है कि पुराना संविधान/सदस्य तब तक कर्तव्य का पालन करता रहता है जब तक कि कोई नया

संस्थान/सदस्य उस कर्तव्य का कार्यभार नहीं संभाल लेता। वर्तमान मामले में भी, एक सदस्यीय न्यायाधिकरण तब तक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता रहेगा जब तक कि राज्य आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं करता। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि दीवानी न्यायालय ऐसी स्थिति में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा क्योंकि यह विधायिका के इरादे से स्पष्ट है कि वे नहीं चाहते कि कोई अन्य प्राधिकरण अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के मामले पर प्रयोग करे।

28. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुच्छला ने प्रस्तुत किया कि 2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा, उप-धारा 83 (4) को अधिनियम की पिछली उप-धारा 83 (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि विधानमंडल का इरादा है कि एक सदस्य न्यायाधिकरण पर्याप्त नहीं है और इसके स्थान पर तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण काम करना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार पुरानी धारा 83 (4) और संशोधित धारा 83 (4) एक दूसरे के साथ असंगत हैं और इसलिए, निहित निरसन का सिद्धांत लागू होगा। दूसरे शब्दों में, संशोधित अधिनियम में उपयोग किए गए प्रतिस्थापन शब्द की व्याख्या निहित निरसन के रूप में की जानी चाहिए। इस संबंध में, विद्वान वकील ने एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त), नगर परिषद, पलाई बनाम टी. जे. जोसेफ, ए. आई. आर. 1963 एससी 1561, और भगत राम शर्मा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. (1988) एससी 740 पर भरोसा किया।

29. हम विद्वान वकील द्वारा की गई इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 1995 अधिनियम की धारा 83 (4) को निहित रूप से निरस्त कर दिया गया है।

30. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां किसी विशेष अधिनियम का कोई निरसन खंड है, यह स्पष्ट निरसन का मामला है, लेकिन जहां निहित निरसन का सिद्धांत लागू किया जाना है, उस मामले को निरसन खंड में उपयोग किए गए शब्दों के सटीक अर्थ और दायरे को

ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि निहित निरसन का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाता है और एक नए अधिनियम द्वारा एक अतिरिक्त उपाय का केवल प्रावधान एक मौजूदा उपाय को दूर नहीं करता है। निहित निरसन के सिद्धांत को लागू करते समय, यह देखना होगा कि क्या स्पष्ट रूप से असंगत प्रावधानों को निरस्त और फिर से अधिनियमित किया गया है।

31. पूर्ववर्ती विधि के निहित निरसन का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब बाद की विधि का अधिनियमन किया गया हो जिसमें पूर्ववर्ती विधि को ओवरराइड करने की शक्ति थी और जो पूर्ववर्ती विधि के साथ पूरी तरह से असंगत है और दोनों विधियां एक साथ नहीं खड़ी हो सकती हैं। यदि बाद का कानून पहले के कानून का स्थान लेने में सक्षम नहीं है, और किसी कारण से इसे लागू नहीं किया जा सकता है, तो पहले का कानून जारी रहेगा। ऐसे मामले में, निहित निरसन के नियम के परिणामस्वरूप एक शून्य हो सकता है जिसका कानून बनाने वाले प्राधिकारी ने इरादा नहीं किया होगा।

32. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1043 के मामले में निहित निरसन के सिद्धांत पर विचार किया था, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः-"पहले के कानून के निहित निरसन का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब बाद के कानून का

अधिनियमन हो जिसमें पहले के कानून को ओवरराइड करने की शक्ति हो और जो पहले के कानून के साथ पूरी तरह से असंगत हो, यानी जहां दो कानून-पहले का कानून और बाद का कानून-एक साथ नहीं खड़े हो सकते।

33. यह एक तार्किक आवश्यकता है क्योंकि दोनों असंगत कानून विरोधाभास के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना मान्य नहीं हो सकते हैं। बाद के कानून पहले के विपरीत कानूनों को निरस्त कर देते हैं। हालाँकि, यह सिद्धांत इस शर्त के अधीन है कि बाद का कानून प्रभावी होना चाहिए। यदि बाद का कानून पहले के कानून का स्थान लेने में सक्षम नहीं है और किसी कारण से इसे लागू नहीं किया जा सकता है, तो पहले का कानून जारी रहेगा। ऐसे मामले में निहित निरसन का नियम आकर्षित नहीं होता है क्योंकि निहित निरसन के नियम के लागू होने के परिणामस्वरूप एक शून्य हो सकता है जिसका कानून बनाने वाले प्राधिकरण ने इरादा नहीं किया होगा। अब, परिशिष्ट II में क्या शामिल है? इसमें विषयों और उनमें से प्रत्येक को दिए गए अंकों की एक सूची होती है। लेकिन हमें कौन बताता है कि विषय की उस सूची का क्या अर्थ है? नियम 11 की उपस्थिति में ही कोई परिशिष्ट-2 के अर्थ और उद्देश्य को समझ सकता है। 1947 के नियमों में नियम 11 को फिर से लागू करने वाले संशोधन के अभाव में, निहित निरसन के सिद्धांत को लागू करके यह मानना मुश्किल है कि 1950 के नियम अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों के मंत्री प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं हुए हैं। उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू

की अनदेखी की और यह निर्णय दिया कि 1947 के नियमों में नए परिशिष्ट-2 को केवल फिर से शामिल करने पर, उक्त परिशिष्ट के अनुसार परीक्षाएँ आयोजित की जा सकती हैं। हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।"

निहितार्थ द्वारा निरसन के विरुद्ध एक धारणा है। इस धारणा का कारण यह है कि विधायिका को किसी कानून को लागू करते समय इस विषय पर मौजूदा कानूनों की पूरी जानकारी होती है और इसलिए, जब वह निरसन प्रावधान प्रदान नहीं कर रही होती है, तो वह मौजूदा कानून को निरस्त नहीं करने का इरादा बताती है। यदि किसी भी निष्पक्ष व्याख्या से, दोनों कानून एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो कोई निहित निरसन नहीं होगा और अदालत को निहित निरसन के खिलाफ झुकना चाहिए। इसलिए, यदि दोनों क़ानून किसी भी उचित कारण से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है और दोनों क़ानूनों को कायम रहने दिया जा सकता है।

34. नगरपालिका परिषद, पलाई बनाम टी. जे. जोसेफ, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1561 के मामले में निहित निरसन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की गई है, इस न्यायालय ने कहाः-"9. यह निस्संदेह सच है कि विधायिका निहितार्थ द्वारा निरसन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यह कानून का एक समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक निहित निरसन के खिलाफ एक धारणा है। इस धारणा

पर कि विधायिका एक ही विषय से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों की पूरी जानकारी के साथ कानून बनाती है, एक निरसन खंड जोड़ने में विफलता इंगित करती है कि इरादा मौजूदा कानून को निरस्त करने का नहीं था। बेशक, इस धारणा का खंडन किया जाएगा यदि नए अधिनियम के प्रावधान पुराने के साथ इतने असंगत हैं कि दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसा कि सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड द्वारा देखा गया है, पृष्ठ 631, पैरा 311: "पुराने और नए कानूनों के दो प्रावधानों के बीच ऐसी सकारात्मक प्रतिकूलता होनी चाहिए जिसे अक्सर कहा जाता है कि उनका मिलान नहीं किया जा सकता है और उन्हें एक साथ खड़ा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में वे पूरी तरह से घृणित या अपरिवर्तनीय होने चाहिए। अन्यथा, पुराने अधिनियम को निरस्त करने के विधायिका के इरादे के लिए कोई निहित निरसन नहीं हो सकता है।

35. उनके लॉर्डशिप्स ने आगे निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः-"इस नियम का कारण कि स्पष्ट विसंगति या प्रतिकूलता की स्थिति में एक निहित निरसन होगा, क्रॉस्बी पैच में इंगित किया गया है और इस प्रकार हैः" जैसा कि कानूनों को विचार-विमर्श के साथ पारित किया जाना माना जाता है, और एक ही विषय पर सभी मौजूदा लोगों की पूरी जानकारी के साथ, यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि विधानमंडल, एक क़ानून पारित करते समय, एक ही मामले से संबंधित किसी भी पूर्व कानून में हस्तक्षेप करने या उसे निरस्त करने का इरादा नहीं रखता था, जब तक

कि दोनों के बीच की असहमति अपरिवर्तनीय न हो। बोवेन बनाम लीज़ (5 हिल 226)। सेडगविक कहते हैं कि यह एक नियम है कि नकारात्मक शब्दों के बिना एक सामान्य क़ानून पहले वाले के विशेष प्रावधानों को निरस्त नहीं करेगा, जब तक कि दोनों अधिनियम अपरिवर्तनीय रूप से असंगत न हों। लेखक कहता है, "नियम का कारण और दर्शन यह है कि जब विधायक का मन किसी विषय के विवरण की ओर मुड़ जाता है, और उसने उस पर कार्रवाई की है, तो सामान्य शब्दों में एक बाद का क़ानून, या विषय को सामान्य तरीके से व्यवहार करना, और मूल अधिनियम का स्पष्ट रूप से खंडन नहीं करना, अधिक विशिष्ट या सकारात्मक पिछले प्रावधानों को प्रभावित करने का इरादा नहीं माना जाएगा, जब तक कि बाद के अधिनियम को ऐसा निर्माण देना बिल्कुल आवश्यक न हो, ताकि उसके शब्दों का कोई अर्थ न हो।" हर्षद एस. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 8 एस. सी. सी. 257 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निहित निरसन के सिद्धांत पर विचार किया और अभिनिर्धारित कियाः - "31. निहित निरसन के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक यह होगा कि क्या अधिनियम के प्रावधान संहिता के प्रावधानों के साथ अपरिवर्तनीय रूप से असंगत हैं कि दोनों एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं या विधायिका का इरादा केवल संहिता के प्रावधानों का पूरक होना था। इस आशय का अधिनियम के प्रावधानों से पता लगाया जाना है। न्यायालय निहित निरसन के खिलाफ

झुकते हैं। यदि किसी भी निष्पक्ष व्याख्या से दोनों कानून एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो कोई निहित निरसन नहीं होगा। यदि संभव हो तो निहित निरसन से बचा जाएगा। हालाँकि, यह सही है कि यदि नया कानून पुराने कानून के साथ असंगत या प्रतिकूल है, तो निहितार्थ द्वारा निरस्त करने के इरादे के खिलाफ धारणा को उखाड़ फेंका जाता है, क्योंकि असंगति या प्रतिकूलता मौजूदा कानूनों को निरस्त करने के इरादे को प्रकट करती है। विरोध इस तरह का होना चाहिए कि दोनों कानूनों का उचित निर्माण या परिकल्पना पर मिलान नहीं किया जा सके। उन्हें स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अपरिवर्तनीय होना चाहिए। यह संभव है, जैसा कि श्री जेठमलानी ने तर्क दिया है, कि विसंगति एक क़ानून के हिस्से पर काम कर सकती है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में निहित निरसन के खिलाफ धारणा का खंडन किया जाता है क्योंकि अधिनियम के प्रावधान पहले के अधिनियमों के प्रावधानों के साथ इतने असंगत या प्रतिकूल हैं कि दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तर्क यह है कि विशेष न्यायालय द्वारा धारा306 और 307 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार विधायिका ने अधिनियम को अधिनियमित करते समय स्पष्ट रूप से इरादा किया कि संहिता के उक्त मौजूदा प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। विद्वान वकील का तर्क है कि यह न्यायालय अधिनियम का इस तरह से अर्थ नहीं निकालेगा जो धारा 376 और 307 या कम से कम उक्त धाराओं का हिस्सा बना देगा और इस

तरह विधायी इरादे को विफल कर देगा, चाहे ऐसी व्याख्या के परिणाम कुछ भी हों। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने एफकॉन्स मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। इस मामले में न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 न्यायालय को दोनों पक्षों की सहमति से मध्यस्थता के लिए एक मुकदमे में पक्षकारों को भेजने का अधिकार देती है। संहिता की धारा 89 और आदेश 10 नियम 1ए के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि धारा 89 के तहत संदर्भ के लिए विचार अनिवार्य है। इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय कानून की व्याख्या के बिंदु पर विभिन्न निर्णयों पर विचार किया जा रहा है और इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा रहा है कि न्यायालय को शाब्दिक निर्माण के नियम का पालन करना होगा जो न्यायालय को विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को लेने का आदेश देता है ताकि इसे वह अर्थ दिया जा सके जो स्वाभाविक रूप से निहित है।

38. मांगिन बनाम आई. आर. सी., (1971) 1 ऑल ई. आर. 179 (पी. सी.) में, प्रिवी काउंसिल ने माना कि एक क़ानून के निर्माण का उद्देश्य विधायिका की इच्छा का पता लगाना है, यह माना जा सकता है कि न तो अन्याय और न ही बेतुकेपन का इरादा था। यदि इसलिए एक शाब्दिक व्याख्या इस तरह का परिणाम उत्पन्न करेगी, और भाषा एक

ऐसी व्याख्या को स्वीकार करती है जो इससे बच जाएगी, तो ऐसी व्याख्या को अपनाया जा सकता है।

39. वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एल. नागेश्वर राव ने सही तर्क दिया है कि धारा 83 (4) को प्रतिस्थापित करते समय संसद का इरादा यह नहीं है कि तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन होने तक एक सदस्य न्यायाधिकरण गायब हो जाए या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। धारा 83 में नई उप-धारा (4) लाने का इरादा और कुछ नहीं बल्कि न्यायाधिकरण के गठन में सुधार है और पूर्व और प्रतिस्थापित दोनों उप-धाराएं एक दूसरे के साथ असंगत नहीं हैं।

40. यहां पहले चर्चा किए गए कानून को ध्यान में रखते हुए और इस मामले में अपने चिंतित विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारी निश्चित राय है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कानून की गंभीर त्रुटि की है कि संशोधन अधिनियम, 2013 लागू होने के बाद, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले एक सदस्यीय न्यायाधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो गया है, भले ही तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने वाली एक नई अधिसूचना अधिसूचित नहीं की गई हो। उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्ति के संबंध में विवादों का फैसला करने के लिए दीवानी न्यायालय को निर्देश देने में कानूनी रूप से गलती की।

41. इसलिए हम एसएलपी (सी) No.30725/2015 से उत्पन्न अपील को छोड़कर सभी अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय

द्वारा पारित विवादित फैसले को खारिज कर देते हैं। नतीजतन, एसएलपी (सी) No.30725/2015 से उत्पन्न अपील को यह मानते हुए खारिज कर दिया जाता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

42. आदेश को छोड़ने से पहले हम उन राज्यों के आचरण के प्रति अपना गंभीर अपवाद दर्ज करते हैं जिन्होंने आज तक अधिनियम की धारा 83 (4) द्वारा अधिदेश के रूप में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन करते हुए नई अधिसूचना जारी नहीं की है।

इसलिए हम राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए तुरंत कदम उठाएं और इस आशय की अधिसूचना आज से चार महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए। इस निर्णय की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अनुपालन के लिए भेजी जाए।

निधि जैन

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सुनील कुमार की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।